आउटकम बजट 2020-21 की स्टेटस रिपार्ट

31 दिसंबर, 2020 तक

सत्यमेव जयते

योजना विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
मार्च 2021

INDEX

क्रम सं.	विभाग	पृष्ठ सं.
I.	भूमिका	01
II.	शिक्षा निदेशालय	08
III.	उच्च शिक्षा निदेशालय	09
IV.	प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय	10
V.	स्वास्थ्य विभाग	11
VI.	समाज कल्याण विभाग	12
VII.	महिला और बाल विकास	13
VIII.	परिवहन विभाग	14
IX.	लोक निर्माण विभाग	15
X.	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	16
XI.	विद्युत विभाग	17
XII.	पर्यावरण विभाग	18
XIII.	वन विभाग	19
XIV.	आउटकम बजट और आगे की राह	20

I. भूमिका

माननीय अध्यक्ष जी,

1. मैं आउटकम बजट 2020-21 के तहत दिसंबर 2020 तक योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों पर सरकार का लगातार चौथा रिपोर्ट कार्ड इस सम्मानित सदन में पेश करते हुए अपना सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ।

2. इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि दिल्ली का आउटकम बजट एक अनूठा दस्तावेज है, जिसने सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। बजट आवंटन अब औसत दर्जे के आउटपुट और आउटकम संकेतक में विभाजित हैं, जिन्हें मॉनिटर करना आसान है।

3. आउटकम बजट दिल्ली सरकार की प्रत्येक प्रमुख योजना और कार्यक्रम के प्रदर्शन को दो प्रकार के संकेतकों में विभाजित करता है : (i) आउटपुट संकेतक, जो हमें बताते हैं कि सरकारी विभागों को किस तरह की सरकारी सेवाएं या बुनियादी ढांचा प्रदान करना चाहिए, जैसे-कितने मोहल्ला क्लीनिक बनाने की योजना है, और (ii) आउटकम संकेतक, जो हमें बताते हैं कि लोगों को उस योजना से कैसे लाभ हुआ है। उदाहरण के लिए, कितने लोग मोहल्ला क्लीनिकों तक पहुंचे। सभी आउटपुट और आउटकम संकेतक मात्रात्मक और मापनीय संख्या में व्यक्त किए जाते हैं जिसमें पूंजीगत परियोजनाओं के लिए समय-सीमा भी सम्मिलित हैं।

4. मैं ''आउटकम बजट 2020-21 की ''स्टेटस रिपोर्ट'' प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो दूसरे शब्दों में, रिपोर्ट कार्ड है,

अर्थात् इस बात का लेखा-जोखा है कि विभिन्न विभागों ने वार्षिक बजट 2020-21 के तहत आवंटित निधि के साथ कैसा कार्य निष्पादन किया है। यह रिपोर्ट कार्ड इस बात का हिसाब देता है कि क्या धन उस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया है, जिसके लिए आवंटित किया गया था और यह भी कि खर्च की गई धनराशि का परिणाम क्या रहा और 31 दिसंबर, 2020 तक आउटपुट और आउटकम के महत्वपूर्ण संकेतकों के सेट के संदर्भ में ऑन-ट्रैक सूचकों का प्रतिशत में किस विभाग का कुल स्कोर क्या रहा है?

5. माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत कोविड-19 महामारी की छाया में हुई और एक कड़ा लॉकडाउन हुआ, जिसने सभी सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों पर विराम लगा दिया। हमारी सरकार ने कोविड-19 महामारी का डंट कर मुकाबला किया, लेकिन इसने सरकार की नियमित गतिविधियों में बहुत बांधा पहुंचाई। राजस्व संग्रह लगभग पूरी तरह डूब गया और सरकार के संसाधनों और प्रयासों का प्रयोग कोविड-19 का असर कम करने के लिए किया गया। इस स्थिति ने लॉकडाउन के साथ मिलकर, आउटकम बजट 2020-21 में निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति और उपलब्धियों को अनिवार्य रूप से प्रभावित किया। ऐसे असाधारण वर्ष में सरकार के काम की सच्ची तस्वीर प्रतिबिंबित करने के लिए हमने आउटकम बजट 2020-21 की स्टेटस रिर्पोट में महत्वपूर्ण संकेतकों की संख्या कम करी है।

6. अध्यक्ष महोदय, अब मैं कोविड-19 महामारी से निपटने में सरकार के प्रयासों का स्नैप शॉट प्रस्तुत करूंगा। इस महामारी से निपटने में सरकार के प्रयासों का वर्णन हमारे फ्रंटलाइन वर्करों-कोरोना यौद्धाओं के साहसिक प्रयासों से शुरू होना चाहिए। मैं इन फ्रंटलाइन वर्करों के लिए दिल्ली के सभी लोगों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कोविड-19 के खिलाफ हमारी सफलता में उन सभी फ्रंटलाइन वर्करों का योगदान रहा है, जो केंद्र, राज्य, स्थानीय निकायों की सरकारी प्रणाली और निजी क्षेत्र के अंतर्गत अग्रणी रहे, यानी डॉक्टर, नर्स, अन्य मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, नगर निगमों के फील्ड कर्मचारी, दिल्ली पुलिस के जवान, डीएम कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी, कोविड संबंधी विभिन्न प्रकार की ड्यूटी करने वाले शिक्षक शामिल हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सिस्टम काम कर रहा था और साथ ही दिल्ली के नागरिकों में विश्वास का माहौल पैदा किया।

राजस्व विभाग

7. लॉकडाउन की घोषणा के साथ शुरू हुए, कोविड-19 महामारी के प्रारंभिक चरण का प्रबंधन हमारे जिला प्रशासनिक अधिकारियों और एसडीएम ने दिल्ली पुलिस के साथ करीबी समन्वय द्वारा किया गया था। लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया गया, कंटेनमेंट जोन की पहचान की गई और उन्हें नियंत्रित किया गया। अनिवार्य सेवाओं और आवाजाही की सुविधा के लिए पास जारी किए गए। लॉकडाउन अनेक लोगों के लिए आर्थिक संकट का एक बड़ा कारण भी बना- चाहे वे वेतनभोगी हों या दिहाड़ी मज़दूर, उन्हें अपनी आमदनी और आजीविका खोनी पड़ी।

8. ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार ने मदद के उपाय शुरू किए। हमारी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि

कोई भी भूखा न सोए। राजस्व विभाग ने 1914 हंगर रिलीफ सेंटर्स की स्थापना की, जिनमें से कई सरकारी स्कूलों में भी थे। यह सभी सेंटर 3 महीने तक चालू रहे। अपने चरम पर, इन केंद्रों ने 10 लाख से अधिक लोगों को दिन में दो बार पका-पकाया भोजन प्रदान किया।

9. इसके अतिरिक्त, 260 रैन बसेरों की स्थापना की गई, जो लॉकडाउन के दौरान बेघर हुए हजारों लोगों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों, जो इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, को मुफ्त में रहने, भोजन और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान की गईं।

10. जब भारत सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए विशेष रेलगाड़ियाँ चलानी शुरू कीं, तो दिल्ली सरकार ने 252 रेलगाड़ियों की बुकिंग की और केंद्र या अपने गृह राज्यों से कोई सहायता लिए बिना 3,12,725 श्रमिकों को घर भेजने के लिए अग्रिम रेल किराए का भुगतान किया। बसों के माध्यम से भेजे गए लोगों को जोड़कर, लगभग 4 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों की यात्राओं के लिए दिल्ली सरकार से सहायता प्राप्त हुई।

11. सर, कोविड-19 ने भी कई फ्रंट लाइन कर्मचारियों को जानमाल का नुकसान पहुंचाया है। हमारी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार थी, जिसने कोविड-19 के दौरान कोविड ड्यूटी निभाते के दौरान जान गंवाने वाले नौ फ्रंटलाइन श्रमिकों के परिवारों को प्रति परिवार 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। हमने दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक-एक मृतक कार्मिक के परिवारों को भी एक-एक करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति

12 लॉकडाउन के दौरान पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के अलावा, दिल्ली सरकार ने पीडीएस के तहत मौजूदा राशन कार्ड धारकों के साथ-साथ राशन कार्ड नहीं रखने वाले लोगों को भी मुफ्त राशन प्रदान किया, जिनमें बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक शामिल थे। अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि में कुल 71 लाख मौजूदा राशन-कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया गया। अप्रैल और मई 2020 के दौरान 60.4 लाख अतिरिक्त गैर-राशन कार्ड धारकों को भी निशुल्क 5 किलोग्राम सूखा राशन प्रदान किया गया, जिसमें 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल शामिल था।

13 इसके अतिरिक्त, राशन कार्ड धारकों सहित 26 लाख लोगों को 8 आवश्यक वस्तुओं का एक किट प्रदान किया गया, जिसमें रिफाइंड तेल, छोले, चीनी, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च और साबुन शामिल था।

स्वास्थ्य

14. दिल्ली सरकार के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी कोविड महामारी का फैलाव रोकना और इसके कारण होने वाली मौतों की संख्या कम से कम करना। कोरोना संक्रमण के तीन लगातार वेव (लहर) के प्रति दिल्ली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और सभी स्वास्थ्य कर्मियों का जो रेसपॉस रहा, चाहे वे डॉक्टर हों, नर्स हों या अर्ध चिकित्सा

कर्मी, एम्बुलेंस चालक या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, वे आज न केवल दिल्ली के लोगों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय हैं।

15. दिल्ली सरकार ने कोविड के खिलाफ एक व्यापक रणनीति अपनाई, जिसमें अधिक से अधिक जांच, होम आइसोलेशन को बढ़ावा देना, कोरोना बेड और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाना और गंभीर कोविड मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरैपी सुनिश्चित करना।

16. 31 दिसंबर 2020 तक, कुल 87.8 लाख कोविड जांच की गई, जिसमें 31.3 लाख आरटी-पीसीआर जांच थी। जिस वक्त कोविड के सबसे ज्यादा केस आ रहे थे, उस दौरान दिल्ली सरकार ने प्रतिदिन 90,000 से भी अधिक जांच की, जो न केवल किसी एक शहर या राज्य में, बल्कि पूरे विश्व में प्रतिदिन जांच की अधिकतम संख्या है। केवल तुलना के तौर पर मैं यह उल्लेख कर रहा हूं, कि जब दिल्ली में प्रति 10 लाख की आबादी पर 4400 जांच प्रतिदिन हो रही थी, उस समय केरल में, जो सर्वाधिक जांच की दृष्टि से देश में दूसरा राज्य था, यह दर प्रतिदिन 2300 जांच की थी। जबकि उस समय समूचे भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन औसतन 1300 जांच हो रही थीं।

17. महोदय, हमारा मानना था कि इस वायरस का फैलाव रोकने का एकमात्र तरीका है ज्यादा से ज्यादा जांच, संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करना, ताकि उससे अन्य लोगों तक संक्रमण न फैल सके और उसे समयबद्ध रूप से होम आइसोलेशन में रखना। यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों, औषधलायों और आम आदमी मोहल्ला क्लीनिकों में 330 जांच प्रयोगशाला/केंद्र बनाए। कुल की गई 87.8 लाख जांच में 6.25 लाख लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जो कुल संक्रमण दर का 7.12 प्रतिशत है।

18. दिसंबर 2020 तक 6,09,322 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके थे, जबकि दुर्भाग्य से 10,536 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस अवधि में कोविड मृत्यु दर 1.68 प्रतिशत रहा।

19. इस अवधि के दौरान संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने विश्व का पहला होम आइसोलेशन कार्यक्रम तैयार किया। इस होम आइसोलेशन का अर्थ था कि रोगी अपने घर की भावनात्मक सुरक्षा में आराम से रहते हुए स्वस्थ हो सकता है। उसके परिवार के सदस्य भी उसी घर में दो सप्ताह के लिए क्वारंटीन रह सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संक्रमण फैलाने का स्रोत न बनें। रोगियों को 10 दिन के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा टेली काउंसिलिंग भी उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने संक्रमण से ठीक हो रहे लोगों के लिए घर पर ही निःशुल्क ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की। कुल 60,042 ऑक्सीमीटर और 3000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए और घर पर रहकर स्वस्थ हो रहे दिल्ली के निवासियों को उपलब्ध कराए गए।

20. महोदय, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या और मृत्यु दर को कम करने के लिए तेजी से कोविड बेड को बढ़ाकर अस्पताल के बुनियादी ढाँचे का समय पर संवर्धन सुनिश्चित किया। सरकारी और निजी

सुविधाओं को शामिल करते हुए, दिल्ली सरकार ने 18718 बेड की क्षमता वाले 135 समर्पित कोविड अस्पताल, 8273 बेड की क्षमता वाले 15 संगरोध/समर्पित कोविड देखभाल केंद्र और 882 बेड की क्षमता वाले 6 कोविड स्वास्थ्य केंद्र, दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराए। कुल मिलाकर, 1,79,241 रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता थी और उन्हें इन संगरोध कोविड देखभाल केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। यह हमारे बेहरत प्लानिंग का एक प्रमाण है कि तीन वेव के बावजूद, हर समय, कोविड बेड की कुल संख्या, कोविड केस की संख्या से दोगुने से अधिक थी।

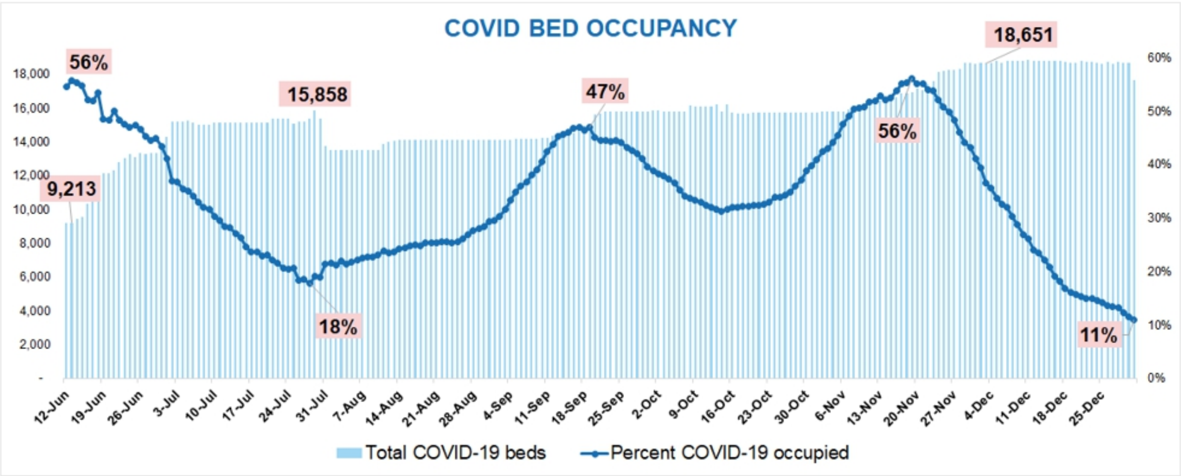

तीन वेव के बावजूद, हर समय कोविड बिस्तरों की कुल संख्या मामलों की संख्या से दोगुने से अधिक थी।

21. दिल्ली में कोविड-19 के लिए 1463 वेंटिलेटर उपलब्ध थे और 6,070 मरीजों ने आईसीयू, बीआईपीएपी, ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ इन वेंटिलेटरों का इस्तेमाल किया, ताकि लक्षणों के बढ़े हुए स्तर से निपटा जा सके।

22. जानकारी संबंधी विसंगतियां दूर करने और अस्पतालों में बेड की स्थिति का पता करने में आने वाली भौतिक परेशानियां कम करने के लिए, सरकार ने एक सरल मोबाइल एप्लिकेशन पेश किया, ताकि सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता का वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध कराया जा सके। ऐसा करके, दिल्ली सरकार समर्पित ''दिल्ली कोरोना एप'' लॉन्च करने वाली देश में पहली सरकार बन गई।

23. दिल्ली कोविड के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य भी बना, जो गंभीर रोगियों के जीवन को बचाने में बहुत फायदेमंद साबित हुई। प्लाज्मा उपचार की प्रभावकारिता को देखते हुए, दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य भी बना, जिसने इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलिएरी साइंसेज और लोक नायक अस्पताल में 2 प्लाज्मा बैंक स्थापित किए। इन दोनो बैंक से 5629 यूनिट प्लाज्मा कोविड-19 मरीजों को दिये गये।

24. महोदय, हमने कोविड-19 रोगियों के लिए एक समर्पित डीजीएचएस हेल्पलाइन भी शुरू की और दिसंबर 2020 तक 1,36,470 कॉलों के जवाब दिए।

शिक्षा

25. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लाभ के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस सन्दर्भ में कई रचनात्मक पहल की गईं, जो उन विद्यार्थियों तक पहुँचने के लिए थीं, जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थे। शिक्षक प्रशिक्षण भी ऑनलाइन आयोजित किए गए।

26. माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 4 अप्रैल 2020 को ''पैरेंटिंग इन द टाइम ऑफ कोरोना'' श्रृंखला प्रारंभ की। इस श्रृंखला के माध्यम से, एसएमएस और आईवीआर जैसी बुनियादी तकनीक की मदद से, हैप्पीनेस करिकुलम और मिशन बुनियाद के तहत दिल्ली सरकार के शिक्षकों और उनके साथ काम करने वाले अन्य संगठनों ने विद्यार्थियों को 50 दिन तक शैक्षिक गतिविधियों से नियमित रूप से अवगत कराया। इन गतिविधियों के माध्यम से, हमने ''हर घर में एक स्कूल और हर माता-पिता एक शिक्षक'' का समर्थन किया। हमने बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कक्षाएं, विषय-वार लाइव कक्षाएं, विशेष गणित कक्षाएं और उद्यमशीलता पर सत्रों की व्यवस्था की।

27. हमने जुलाई से सेमी-ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कीं, जिसमें हर रोज, केजी से कक्षा 10 तक के बच्चों को व्हाट्सएप पर कार्य पत्रक भेजे गए और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, उनके माता-पिता द्वारा स्कूलों से प्रिंट आउट लेने का विकल्प उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार के शिक्षकों ने कक्षा 11 और 12 के लिए लाइव कक्षाएं संचालित कीं।

28. मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने इस सत्र में कुल 229 दिनों तक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक गतिविधियाँ संचालित की हैं। एक सत्र सामान्य रूप से लगभग 220 दिनों का होता है। इसके साथ, लगभग 98%बच्चों को व्हाट्सएप या प्रिंट के रूप में कार्य पत्रक मिले हैं और उनमें से 83% ने उन्हें दी गई गतिविधियों को पूरा करके अपने शिक्षकों को वापस दे दिया है। इसके साथ ही, कक्षा 11 और 12 के बारह विषयों के लिए आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में 89% - 98% तक बच्चों ने भाग लिया है।

29. शिक्षा विभाग के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कक्षा-12 के लगभग 1.64 लाख विद्यार्थियों में से 1.09 लाख विद्यार्थी शैक्षिक और व्यावसायिक मार्ग दर्शन परामर्श दाताओं के माध्यम से एक काउंसलिंग में शामिल हुए। इससे माता-पिता और बच्चों को कैरियर के बारे में विकल्प चुनने में मदद मिली। इस संबंध में, सीजीसीसी पोर्टल विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ-साथ कैरियर संबंधी जानकारी और विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश सूचना भी देता है।

30. कोविड-19 के बावजूद, स्कूलों ने कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया और छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन भी प्रदान किए गए।

31. कोविड-19 के दौरान मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सभी पात्र विद्यार्थियों

को पके-पकाए भोजन के बदले खाद्य सुरक्षा भत्ते का भुगतान मार्च 2020 से जून 2020 के दौरान किया गया। जुलाई से दिसंबर 2020 की अवधि के लिए, मिड डे मील के बदले विद्यार्थियों को सूखे राशन की किट प्रदान की जा रही है।

उच्च शिक्षा

32. उच्च शिक्षा में, कॉलेजों/विश्वविद्यालयों ने भी अनेक उपाय किए, जैसे कि विद्यार्थियों की गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यूट्यूब सत्र, फेसबुक आदि विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से शिक्षण और असाइनमेंट देने के लिए ऑनलाइन पद्धति का उपयोग करना। शिक्षण के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। विद्यार्थियों के लिए किताबें और पढ़ने की सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई। विद्यार्थियों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं, ऑनलाइन अध्ययन, संदर्भ सामग्री और सामान्य रूप से उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में समय-समय पर परामर्श दिया गया।

यातायात

33. दिल्ली सरकार ने कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से कार्य-संचालन में असमर्थ 18,111 परमिट धारकों और 1,38,239 पीएसवी बैज धारक पैरा-ट्रांजिट सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे ऑटो रिक्शा, टैक्सी, फटफट सेवा, इको-फ्रेंडली सेवा, ग्रामीण सेवा, स्कूल कैब्स, मैक्सी कैब्स के और ई-रिक्शा मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

श्रम विभाग

34. ऐसे निर्माण श्रमिकों, जिन्हें लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ा, उनकी सहायता के लिए दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत लगभग 44,683 निर्माण श्रमिकों को प्रति श्रमिक 10,000 रुपए की नकद सहायता प्रदान की। यह भारत में किसी भी राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे अधिक नकद सहायता है। इसके बाद पंजाब और केरल का स्थान है, जिन्होंने प्रति श्रमिक 3,000 रुपए की सहायता दी है।

35. रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार के आउटकम बजट 2020-21 में सभी प्रमुख विभागों और एजेंसियों को 8 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। सरकार की कुल 595 योजनाएं हैं, जिनमें 1391 यूनीक आउटपुट संकेतक और 1122 यूनिक आउटकम संकेतक शामिल हैं। आउटपुट और आउटकम संकेतकों के प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक विभाग की प्रगति को वर्गीकृत किया गया है। अगर उनकी उपलब्धि संदर्भ समीक्षा अवधि के अनुपात के तहत लक्ष्य प्रगति का 75 प्रतिशित है तो उन्हें ''ऑन-ट्रैक'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अगर उपलब्धि अनुपात के 75 प्रतिशत से कम है, तो उन्हें ''ऑफ-ट्रैक'' वर्ग में रखा गया है।

36. महोदय, मैं अब प्रमुख विभागों के संबंध में आउटकम बजट 2020-21 की स्थिति प्रस्तुत करूंगा।

II. शिक्षा निदेशालय

1. 2020-21 के आउटकम बजट में 37 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गई हैं, जिनमें 182 आउटपुट/आउटकम संकेतक थे। इनमें से 44 महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

2. प्रगति दर्शाने वाली पाई चार्ट

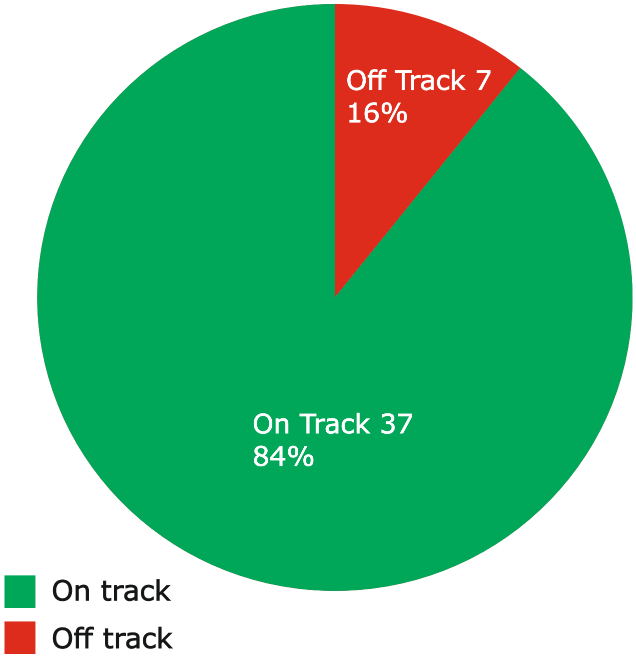

3. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 35275 विद्यार्थियों का निजी स्कूलों में दाखिल कराया गया।
- सरकारी स्कूलों ने 12वीं के स्तर पर शिक्षा सत्र 2019-20 में 97.92 प्रतिशत का उत्तीर्णता प्रतिशत दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह 94.24 प्रतिशत था। 10वीं कक्षा के स्तर पर सरकारी स्कूलों का उत्तीर्णता प्रतिशत 82.61 रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 71.58 प्रतिशत था।
- सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षाओं के 7.87 लाख विद्यार्थी वर्ष 2020-21 के दौरान मिड-डे मील योजना से लाभान्वित हुए।
- 728 सरकारी स्कूल भवनों में से 459 में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम पूरा हो गया है।

III. उच्च शिक्षा निदेशालय

1. 2020-21 के आउटकम बजट में 13 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गई हैं, जिनमें 234 आउटपुट/आउटकम संकेतक हैं। इन संकेतकों में से 61 महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

2. प्रगति दर्शाने वाली पाई चार्ट

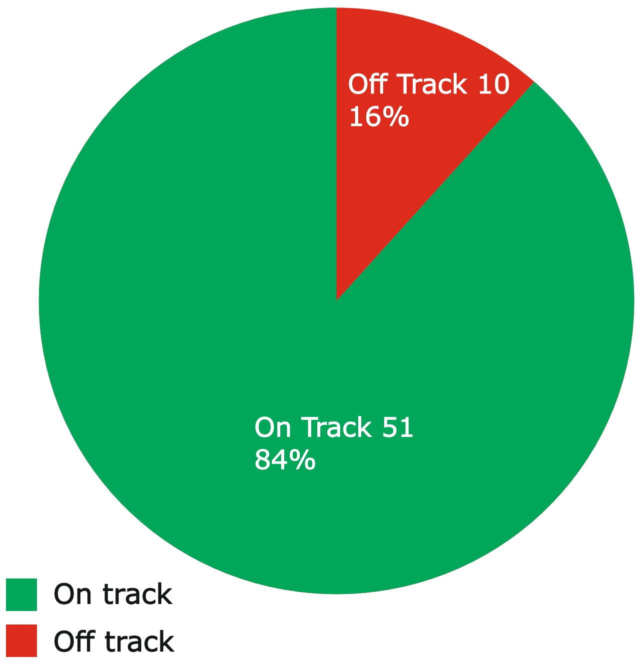

3. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति

- गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी कैंपस का निर्माण कार्य अगस्त 2017 में शुरू किया गया था। लोक निर्माण विभाग ने दिसंबर 2020 तक 80 प्रतिशत प्रगति की रिपोर्ट दी है।

- दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में वर्ष 2020-21 में कुल 8248 नए विद्यार्थी नामांकित किए गए। वर्ष 2019-20 के दौरान 7539 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था।

- वर्ष 2020-21 के दौरान मेरिट कम मीन्स लिक्ंड फाइनेंशियल असिसटेंस स्कीम के तहत 3760 विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

IV. प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय

1. आउटकम बजट 2020-21 में 26 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गई जिनमें 331 आउटपुट/आउटकम संकेतक हैं। इनमें से 129 महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

2. प्रगति दर्शाने वाली पाई चार्ट

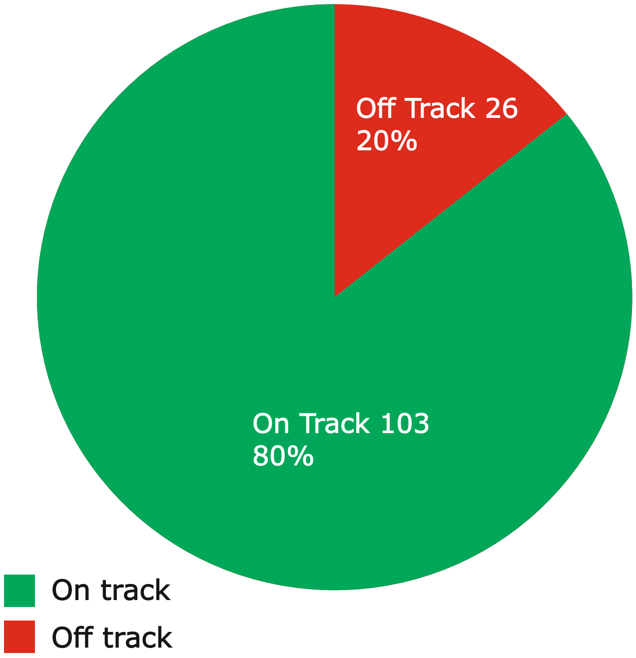

3. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति

- शिक्षा सत्र 2021 में यूजी और पीजी तकनीकी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या बढकर 9591 हो गई, जबकि वर्ष 2019-20 में यह संख्या 8423 थी।

- वर्ष 2020-21 के दौरान दिसंबर माह तक पॉलिटैक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 4100 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, जबकि वर्ष 2019-20 में नए प्रवेश की संख्या 4600 थी।

- वर्ष 2020-21 में दिसंबर माह तक पीएचडी कार्यक्रम में 393 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया और 106 विद्यार्थियों को पीएचडी डिग्री प्रदान की गई। पिछले शिक्षा सत्र में पीएचडी कार्यक्रम में 268 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था, 80 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई थी।

- वर्ष 2020-21 में दिसंबर तक विभिन्न तकनीकी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे 2798 विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट मिला। वर्ष 2019-20 में यह संख्या 3008 थी।

- वर्ष 2020-21 में दिसंबर महीने तक 530 फैकल्टी के 1581 शोध पत्र प्रकाशित हुए। वर्ष 2019-20 में 494 फैकल्टी के 985 शोध पत्र प्रकाशित हुए थे।

V. स्वास्थ्य विभाग

1. आउटकम बजट 2020-21 में 56 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गईं, जिनमें 1616 आउटपुट/आउटकम संकेतक थे। इनमें से 499 महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

2. प्रगति दर्शाने वाली पाई चार्ट

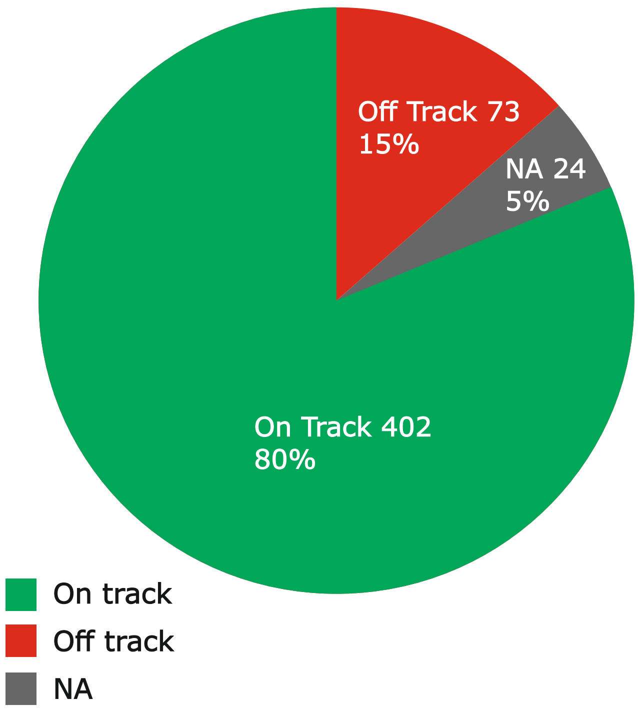

3. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति

- दिसंबर 2020 तक 496 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए गए, जबकि लक्ष्य 750 क्लिनिक का था। औसतन प्रत्येक आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक प्रतिदिन 97 रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है।
- वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 9 से 11 महीने की आयु वर्ग के लगभग 1.82 लाख बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया। वार्षिक लक्ष्य 2.96 लाख बच्चों के टीकाकरण का था।
- आशा कार्यकर्ताओं ने 1.20 लाख संस्थागत प्रसव कराए।
- दिसंबर 2020 तक टीबी से ग्रस्त 59,646 रोगियों का उपचार किया गया।
- दिसंबर 2020 तक औषधि नियंत्रण विभाग ने लगभग 3073 बिक्री कंपनियों का निरीक्षण किया और नियमों का उल्लंघन करने वाले 397 के लाईसेंस निलंबित या रद्द कर दिए।

VI. समाज कल्याण विभाग

1. आउटकम बजट 2020-21 में 29 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गईं, जिनमें 187 आउटपुट/आउटकम संकेतक थे। इनमें से 87 महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

2. प्रगति दर्शाने वाली पाई चार्ट

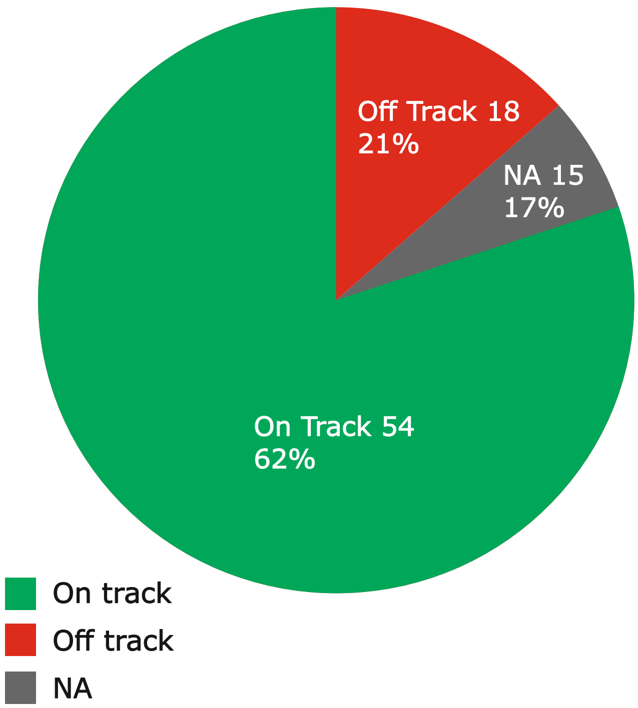

3. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति

- वर्ष 2020-21 में लगभग 4.49 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2019-20 में यह संख्या लगभग 4.64 लाख थी।
- 2020-21 में 1.06 लाख दिव्यांगों को वित्तीय सहायता दी गई। 2019-20 में यह संख्या 95324 थी।
- वर्ष 2020-21 में ऐसे 11145 परिवारों को एक बार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई, जिनके भरण-पोषण करने वाले मुखिया की मौत हो गई थी। पिछले वर्ष 10729 परिवारों को यह सहायता दी गई थी।

VII. महिला और बाल विकास विभाग

1. आउटकम बजट 2020-21 में 25 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गईं, जिनमें 200 आउटपुट/आउटकम संकेतक हैं। इनमें से 151 महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

2. प्रगति दर्शाने वाली पाई चार्ट

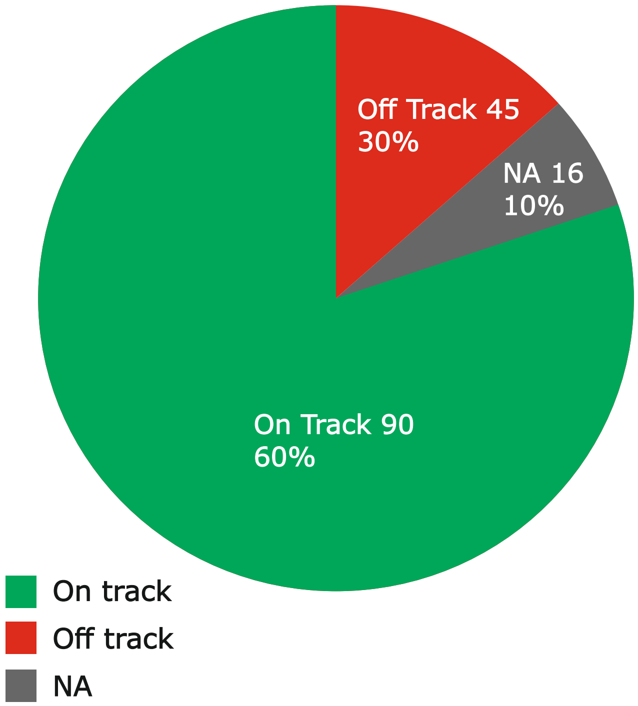

3. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति

- वर्ष 2020-21 में लगभग 2.75 लाख विपत्तिग्रस्त महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2019-20 में 2.66 लाख विपत्तिग्रस्त महिलाओं को वित्तीय मदद दी गई थी।
- लाडली योजना में विभाग ने दिसंबर 2020 तक नए नामांकन (जन्म और विद्यालय स्तर) के लिए 33241 आवेदन प्राप्त किए। वार्षिक लक्ष्य 65,000 का था। लगभग 3304 का नामांकन दिसंबर 2020 तक किया गया।
- लगभग 13 लाख बच्चों और गर्भवती/ स्तनपान कराने वाली माताओं को आईसीडीएस के तहत 10755 आंगनवाडी केंद्रों के माध्यम से पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवा और प्री स्कूल सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

VIII. परिवहन विभाग

1. आउटकम बजट 2020-21 में 24 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गईं, जिनमें 248 आउटपुट/आउटकम संकेतक थे। इनमें से 34 महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

2. प्रगति दर्शाने वाली पाई चार्ट

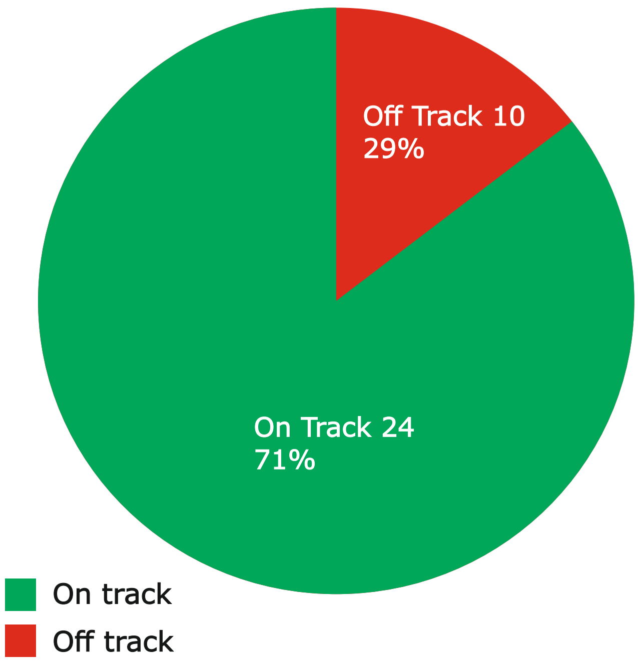

3. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति

- लॉकडाउन के कारण 31 मार्च 2020 से 18 मई 2020 तक बस सेवाएं निलंबित रहीं। डीडीएमए के दिनांक 18.05.2020 के आदेश द्वारा राज्य के अंदर बसों को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई कि एक फेरे में यात्रियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के कार्य निष्पादन पर असर पडा।

- कलस्टर बसों का औसत फ्लीट उपयोग प्रतिशत बढकर 98.58 प्रतिशत हो गया, जबकि लक्ष्य 97 प्रतिशत का था। कलस्टर बसों का ऑनटाइम परफारमेन्स 50 प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में बढकर 69.46 प्रतिशत हो गया।

- डीटीसी बसों का औसत फ्लीट उपयोग प्रतिशत घटकर 73.71 प्रतिशत पर आ गया, जबकि लक्ष्य 90 प्रतिशत का था। डीटीसी बसों का ऑनटाइम परफारमेन्स प्रतिशत घटकर 73 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 68.09 प्रतिशत पर आ गया।

- दिसंबर 2020 तक 47.78 लाख प्रदूशण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी किए गए। लक्ष्य 75 लाख का रखा गया था।

- परिवहन विभाग ने 07.08.2020 को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी अधिसूचित कर दी। इसके बाद से 4924 नए इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन पंजीकृत किए गए। दिसंबर 2020 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीददारों में से 76 प्रतिशत को प्रोत्साहन राशि का वितरण कर दिया गया है।

- 5200 डीटीसी और कलस्टर बसों में दिसंबर 2020 तक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए थे।

- घुम्मनहेरा और मुंडेरा कला में दो बस डिपो का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

IX. लोकनिर्माण (सडक और पुल) विभाग

1. आउटकम बजट 2020-21 में 37 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गईं, जिनमें 446 आउटपुट/आउटकम संकेतक थे। इनमें से 52 महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

2. प्रगति दर्शाने वाली पाई चार्ट

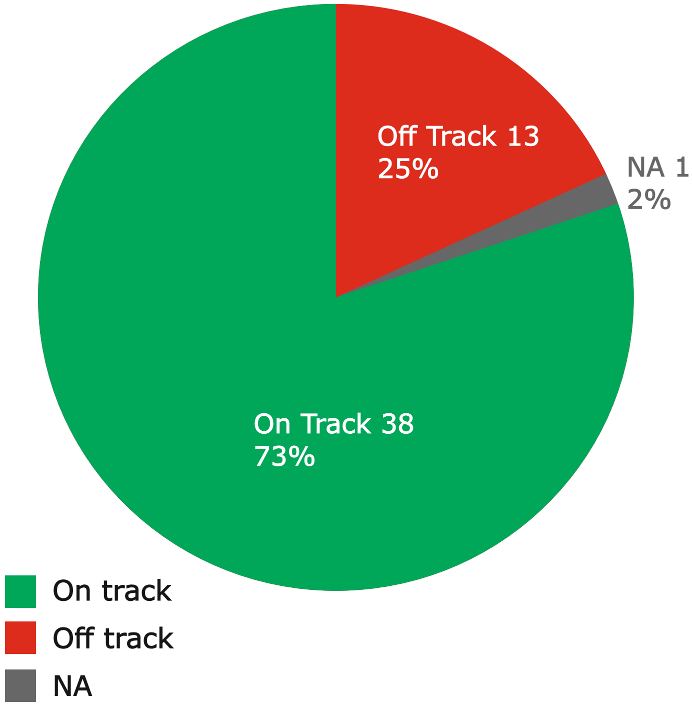

3. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति

- विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आम लोगों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर 1.32 लाख सीसीटीवी कैमरे (चरण 2) लगाए गए। जिसका लक्ष्य भी 1.32 लाख सी सी टी वी कैमरे लगवाने का था।
- शास्त्री पार्क इंटरसैक्शन और सीलमपुर में फ्लाईओवर का काम पूरा कर लिया गया है और इसे 19.10.2020 को लोगों के लिए खोल दिया गया।
- बसई दारापुर में नजफगढ नाले पर पुल को चौडा करने का 65 प्रतिशत कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा कर दिया गया था।
- वजीराबाद और जगतपुर के बीच दो आफ अंडर पास तथा आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट एक पैदल पारपथ का 56 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। आश्रम चौक पर अंडर पास के निर्माण का 40 प्रतिशत कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा कर लिया गया है।
- दिल्ली में दिसंबर 2020 तक 7000 हॉटस्पाट बनाए गए हैं।
- पांच फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। चार फुटओवर ब्रिज का 90 प्रतिशत से अधिक काम दिसंबर 2020 तक पूरा हो चुका है।

X. दिल्ली जलबोर्ड (डीजेबी)

1. आउटकम बजट 2020-21 में 21 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गई, जिनमें 204 आउटपुट/आउटकम संकेतक थे। इनमें से 68 महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

2. प्रगति दर्शाने वाली पाई चार्ट

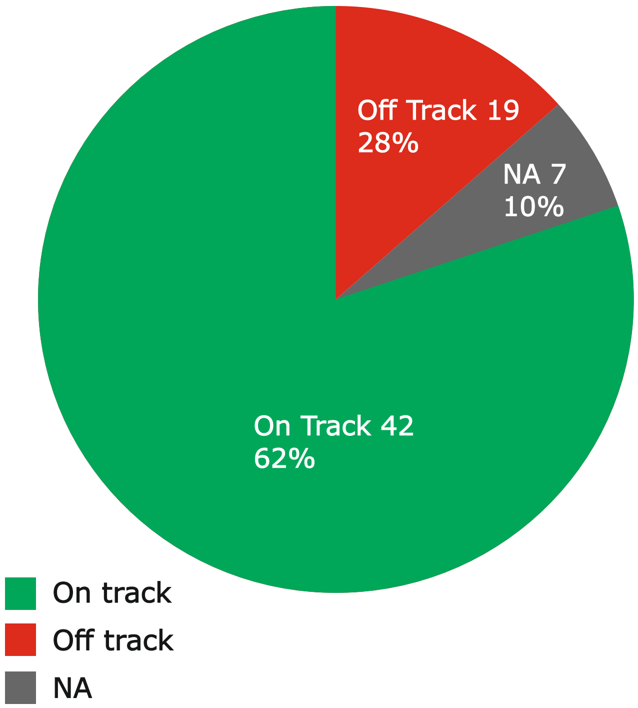

3. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति

- दिसंबर 2020 तक 1571 अनाधिकृत कालोनियों को पानी की पाइप लाईन से जोडा गया। इससे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर टैंकर की संख्या में कमी आई।
- दिसंबर 2020 तक अनाधिकृत कालोनियों में 4743 किलोमीटर पाइप लाईन बिछाई गई।
- दिसंबर 2020 तक कुल 2667.05 किलोमीटर की पुरानी/खराब पाइप लाइन को बदला गया, इससे 3 एमजीडी पानी की बचत हुई।
- प्रतिमाह 20 किलोलीटर नि:शुल्क पानी देने की योजना 2020-21 में जारी रखी गई और लगभग 6.58 लाख उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 44 करोड रूपए की सब्सिडी दी गई।
- दिसंबर 2020 तक अनाधिकृत कालोनियों में कुल 2735 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई गई और 602 अनाधिकृत कालोनियों को सीवर नेटवर्क से जोडा गया।
- दिसंबर 2020 तक नियमित अनाधिकृत कालोनियों में कुल 1221 किलोमीटर पुरानी सीवर लाइन बदली गई।

XI. विद्युत विभाग

1. आउटकम बजट 2020-21 में 15 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गईं, जिनमें 108 आउटपुट/आउटकम संकेतक थे। इनमें से 52 महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

2. प्रगति दर्शाने वाली पाई चार्ट

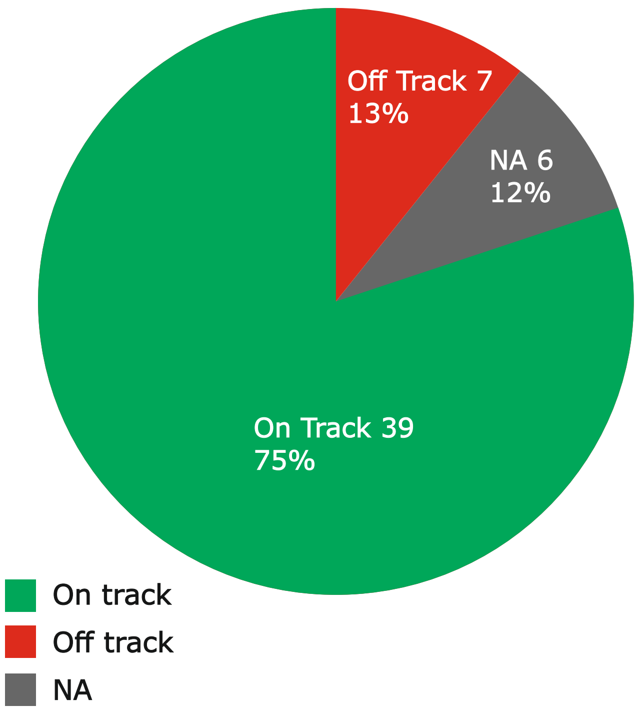

3. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति

- दिसंबर 2020 में ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता बढकर 99.26 प्रतिशत हो गई।
- अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान दिल्ली ने 6314 मेगावॉट की पीक डिमांड पूरी की।
- 2019-20 में एटी एंड सी लॉस 8.66 प्रतिशत रही।
- बिजली विभाग ने 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली शुल्क में शत-प्रतिशत की सब्सिडी दी और 201 से 400 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं को 800 रुपए प्रतिमाह तक की सब्सिडी दी गई, इससे 36.50 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा हुआ। ये संख्या कुल घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का लगभग 89 प्रतिशत है।
- दिसंबर 2020 तक दिल्ली में 185 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। लक्ष्य 300 मेगावाट का था। इन संयंत्रों से 501 मेगा यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। वार्षिक लक्ष्य 500 मेगा यूनिट का था।

XII. पर्यावरण विभाग

1. आउटकम बजट 2020-21 में 19 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गईं, जिनमें 132 आउटपुट/आउटकम संकेतक थे। इनमें से 33 महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

2. प्रगति दर्शाने वाली पाई चार्ट

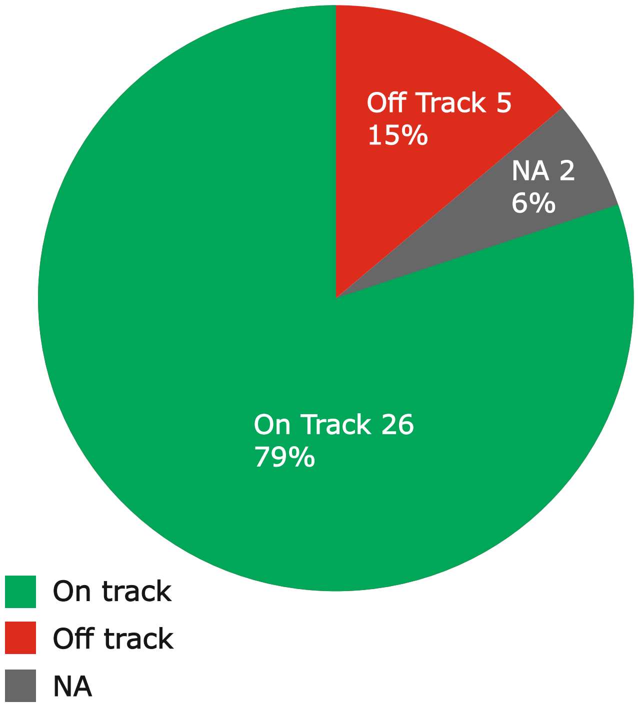

3. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति

- सभी 26 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र सुचारू हैं।
- उद्योग, बिजली संयंत्र, होटल इत्यादि से होने वाले उत्सर्जन के 621 सैंपल का दिसंबर 2020 तक परीक्षण किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान 700 नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य था।
- दिसंबर 2020 तक बैटरी संचालित टू व्हीलर के लिए 1747 लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई
- दिसंबर 2020 तक बैटरी चालित फोर व्हीलर के लिए 771 लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई।
- महात्मा गांधी जलवायु परिवर्तन रोकथाम संस्थान द्वारा 44 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिसंबर 2020 तक चलाए गए, जिनमें 2768 प्रतिभागी ञ्शामिल हुए। लक्ष्य 3000 प्रतिभागियों का था।

XIII. वन विभाग

1. आउटकम बजट 2020-21 में 8 कार्यक्रम/स्कीम शामिल की गईं, जिनमें 115 आउटपुट/आउटकम संकेतक थे। इनमें से 89 महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

2. प्रगति दर्शाने वाली पाई चार्ट

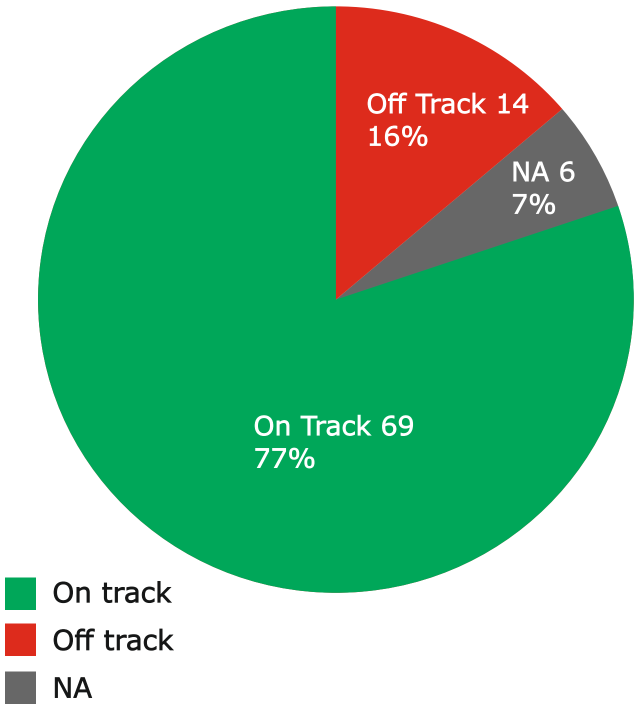

3. महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति

- दिसंबर 2020 तक ईटीएफ द्वारा तीन लाख पौधे लगाए गए। 2020-21 के दौरान 2.50 लाख पौध रोपण का लक्ष्य था।
- दिसंबर 2020 तक अभयारण्य से बाहर 1.91 लाख पौधे लगाए गए। वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य 1.93 लाख का है।
- दिसंबर 2020 तक 3.88 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। 2020-21 के दौरान 3.50 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य है।
- शहरी वनों का सृजन और प्रबंधन योजना के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक 05 शहर वन सृजित किए गए और प्रबंधित किए गए। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 05 शहरी वनों का ही लक्ष्य था।

XIV. आउटकम बजट और आगे की राह।

37. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का व्यापक आउटकम बजट बेजोड़ बजटीय पहल है, जो योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी की प्रक्रिया को बदल रहा है। यह न केवल आम जनता और हमारे विभागों के लिए एक उपकरण है, बल्कि शोधकर्ताओं के लिए विभिन्न विभागों के कामकाज और उनके कार्यक्रमों का अध्ययन करने का एक दस्तावेज भी है। यह ऐसा दस्तावेज है, जिसका देश भर के राज्यों द्वारा अनुकरण किया जा सकता है।

38. आउटकम बजट के संदर्भ में विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा एक पहल है, जो सरकार का एक अतुलनीय और साहसिक कदम है, जो वर्ष के अंत में मात्रात्मक और पारदर्शी तरीके से किए गए कार्य का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। विभाग अब अधिक सक्रिय हैं और अधिक लक्ष्य उन्मुखी दृष्टिकोण के साथ काम करते हैं, जिससे बेहतर परिणाम हासिल होते हैं।

39. आउटकम बजट शासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गया है और सरकार को उनके प्रदर्शन के आधार पर सभी विभागों को रैंक करने में मदद करता है।

40. आउटकम बजट 2021-22 को तैयार करने की कवायद योजना विभाग द्वारा पहले ही शुरू कर दी गई है और आउटकम बजट की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को मई 2021 के अंत तक भेज दी जाएगी और इसे योजना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा। यह अपनी नियमित निगरानी के लिए वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न संकेतकों के लक्ष्य में 2020-21 की उपलब्धियां पेश करेगा।

योजना विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार